sels can avail of the facility of duty free import of inputs for manufacture in bond of such vessels in terms of notification No. 237/87-Customs, dated 16th June, 1987 and no duty is charegeable on such inputs.

Special Investigation Team on assassination of Mrs. Indira Gandhi

1913. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Special Investigation Team which probed the assassinaion of Mrs. Indira Gandhi has since been wound up; and

(b) if so, what are the reasons for the resignation of the Special Commissioner of the SIT when the conspiracy case regarding Mrs. Gandhi's assassination is still in progress?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) Shri S. Anandaram, Special Commisioner of Police, S.I.T., after retirement was re-employed upto 31st May, 1989 and was permitted to demit his office on expiry of his re-employment.

इलाहाबाद में बोट क्लब का निर्माण और यमुना नदी के घाटों का नवीकरण

@1914. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आमोद-प्रमोद संबंधी क्रियाकलापों के लिए इलाहाबाद में यमुना नदी के विकास के लिए एक बोट क्लब शुरु करने तथा नेहरू घाट पर घाटों आदि का नवीकरण करने के लिए जो परियोजना है, उस पर काम के कब तक शुरु हो जाने की संभावना है ; और

@ पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1326, 28 जुलाई, 1989 से स्थानांतरित

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख) सार्वजनिक सुविधाओं, स्नान सुविधाओं, नेहरु घाट का विकास और वतमान घाटों की मरम्मत आदि कार्यों वाली सरस्वती घाट के एकीकृत विकास की एक परियोजना का कार्य शुरु हो चुका है । इस परियोजना के मार्च, 1990 तक पूरा होने की संभावन है ।

'माडवेट' स्कीम इत्यादि के लेखा परीक्षा कार्य को चार्टर्ड एकाउन्टेंटों को सौंपा जाना

1915. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्पाद शुल्क माडवेट स्कीम तथा सरकारी सेवा संस्थाओं से संबंधित लेखा परीक्षा कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेंटों को सौंपने के लिए कानूनी उपबंध करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार सभी राज्यों की सहकारिताओं के लेखा परीक्षा कार्य को अनिवार्य बनाने का विचार भी रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) जी नहीं ।

(ख) सहकारिता राज्य का विषय है । इस संबंध में भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।